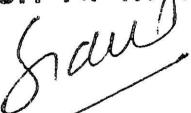


कागजात प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

(राज्य सभा/लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु)

संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब तथा तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण में समय लगने के कारण हुआ।

अधिप्रमाणित


(प्रकाश जावडेकर)
सूचना एवं प्रसारण मंत्री

राज्य सभा/लोक सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु कागजात

नई दिल्ली

अधिप्रमाणित

दिनांक

(प्रकाश जावडेकर)

सूचना एवं प्रसारण मंत्री

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा

1. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) की स्थापना 1975 में की गई थी (भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व) जिसका प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय फ़िल्म उद्योग का व्यवस्थित, प्रभावशाली एवं समग्र रूप से विकास। एनएफडीसी को 1980 में एनएफडीसी के साथ पूर्ववर्ती फ़िल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आईएमपीएसी) को मिला कर पुनः सम्मिलित कर दिया गया। एनएफडीसी ने अब तक 300 से भी अधिक फीचर फ़िल्मों का निर्माण / वित्त पोषण किया है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनाई गई इन फ़िल्मों को व्यापक सराहना मिली और इन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में पुरस्कार प्राप्त किये।
2. निगम ने वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्यतः कमीशंड प्रॉडक्शन के कारण वर्ष के दौरान किये गये इवेन्ट मैनेजमेंट गतिविधियों से रु.14.54 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वर्ष के दौरान जो इवेन्ट्स सफलतापूर्वक संपन्न हुए उनमें प्रमुख हैं, आउटरीच प्रोग्राम “मोडीफेस्ट”, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2017 और “पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018”। जिसकी वजह से संचित हानि का एक बड़ा हिस्सा कम किया जा सका। जोकि 31.03.2018 तक रु. 9.36 करोड़ था। निगम ने पिछले 2 वर्षों से लगातार लाभ दर्ज किया है।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना के अंतर्गत “विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्म निर्माण” शीर्षक के अंतर्गत फ़िल्म निर्माण विभाग ऐसी फ़िल्मों का निर्माण अथवा सह निर्माण करता है जिसके अनुसार एनएफडीसी द्वारा उनके फ़िल्म निर्माण के विस्तारित उपनियमों के अंतर्गत प्रशंसित फ़िल्म कारों के साथ फ़िल्मों का निर्माण/ सहनिर्माण किया जाता है। एनएफडीसी ने फ़िल्म निर्माण पर मंत्रालय के प्लैन स्कीम के अंतर्गत हिन्दी सहित 14 भाषाओं में 18 नवोदित फ़िल्मकारों उनकी पहली निर्माण/सहनिर्माण फ़िल्मों द्वारा पहचान दी।
4. वर्ष के दौरान, एनएफडीसी ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 1 करोड़ के सामने न्यूज़ीलैंड फ़िल्म कॉर्पोरेशन और भारतीय फ़िल्म निर्माता के साथ पैन नलिन द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'बियोंड द नॉन वर्ल्ड' के लिये सह निर्माण करार साझन किया है।
5. एनएफडीसी लाइब्रेरी कैटलोग सभी लोकप्रिय प्लेटफार्म्स जैसे अमेझॉन प्राइम वीडियो, नेटफिलक्स, हॉटस्टार, जिओ मुवीज तथा जी एंटरटेनमेंट पर हैं।
6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विदेशी फ़िल्म निर्माताओं द्वारा भारत में फ़िल्म शूटिंग को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान, अनुमतियाँ प्रदान करने के अलावा, एफएफओ द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की गईं:
 - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (एनआईसीएसआई) के माध्यम से एफएफओ अपना वेब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। पोर्टल की स्थापना के लिए सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी 29 सर्कल्स में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की सुविधा।

- सोलह राज्यों ने मोस्ट फ़िल्म फ्रैंडली स्टेट अवार्ड 2017 में भाग लिया, जिसे 65 वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के प्रायोजन में दिया गया था। मोस्ट फ़िल्म फ्रैंडली स्टेट अवार्ड 2017 मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया तथा उत्तराखण्ड राज्य को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
7. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एनएफडीसी को भारत के 48 वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (ईफी) के आयोजन का कार्य सौंपा गया था। ईफी 2017 के साथ फ़िल्म बाजार के 11 वें संस्करण का आयोजन एनएफडीसी द्वारा किया गया था और अपने स्व निधियों से वित्त पोषित किया गया था। फ़िल्म बाजार के इस संस्करण में कनाडा और नैदरलैंड के देश शिष्टमंडल सहित 38 देशों के 1010 प्रतिनिधि की उपस्थिति दर्ज की गई।
